(ख) यदि हां, तो यह जांच कब तक करवाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की 2-5-76 को सुश्री लाहिरी हत्याकाण्ड की जांच का कार्य सौंपा गया था । जांच के दौरान, हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधी के रूप में पांच व्यक्तियों का पता लगाया गया । उनमें से दो इकबाली गवाह बन गए और सक्षम न्यायालय द्वारा क्षमा दान दे दिया गया । शेष तीन अपराधियों को न्यायालय में आरोप-पत्र दे दिए गए और उनके खिलाफ अब मुकद्दमा चल रहा है । केन्द्रीय सरकार का इस मामले में और आगे कोई जांच करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

Manufacture of Cars in collaboration of Mercedes Benz

2119. SHRI P. K. DEO: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Tatas had applied in the past for manufacture of cars in collaboration with Mercedes Benz; and

(b) if so, whether Government are considering to issue licence to them to manufacture small diesel cars in view of scarcity of petrol?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No such application was received in the Ministry of Industry.

(b) He does not arise.

Typewriting tests for L.D.Cs.

2120. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have issued orders asking about 1000 LDCs now working in various ministries to go because they failed to pass the typewriting examination;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) whether this step is in line with Government's "austerity and economy plan"?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). Notices have been served on about 600 LDCs recruited on the basis of examinations held from 1964 to 1973, who have failed to pass the prescribed typing test, to the effect that their services will stand terminated if they do not pass the prescribed test by 30th June, 1977. Keeping in view the exigencies of the situation, it has, however, been decided to grant a final extension of one year to the LDCs who have not passed the test so far. This period will not be extended.

(c) The steps taken have no correlationship with the Government's austerity and economy plan.

सीमेंट का आवंटन

2121. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया सीमेन्ट की एजेंसियां आवंटित करने में क्या मानदण्ड अपनाती है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आगरा और मेरठ डिवीजनों में जिन व्यक्तियों को एजेंसियां दी गईं उनके नाम और पते क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि इन एजेंसियों को देने से सम्बन्धित व्यक्तियों से काफी मात्रा में धन गैर-कानूनी रूप से लिया जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन एजेंसियों के आवंटन के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति करने का है जिससे भ्रष्टाचार में कमी हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मन्त्री (श्री विज लाल वर्मा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा स्टाकिस्ट नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित कसौटी अपनायी जाती है :—

(1) सहकारी समितियों, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारियों और बेरोजगार स्नातकों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(2) निगम की अपनी नीति ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे स्टाकिस्ट नियुक्त करने को प्राथमिकता देने की है ताकि आन्तरिक क्षेत्रों में भी सीमेंट पहुंच सके ।

(3) ऊपर उल्लिखित कोटियों से इतर वर्गों के स्टाकिस्ट नियुक्त करते समय सीमेंट व्यापार और इससे सम्बद्ध व्यापार कार्यों जैसे भवन निर्माण सामग्री में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के मामलों पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

(4) स्टाकिस्ट नियुक्त करते समय क्षेत्र विशेष में सीमेंट की खपत की सम्भाव्यता पर भी ध्यान दिया जाता है ।

(5) मुख्य रूप से 'क'. 'ख'. 'ग' और 'घ' चार श्रेणियों के स्टाकिस्ट नियुक्त किए जाते हैं जिनका मासिक कोटा क्रमश: 75, 50, 25 और 10 मी० टन होता है । आखिर में बताई गई श्रेणी के स्टाकिस्टों की नियुक्ति कारखानों के समीपवर्ती क्षेत्रों में की जाती है जहां सीमेंट ट्रकों अथवा बैलगाड़ियों से भी भर कर भेजी जा सकती है ।

2. मेरठ और आगरा प्रक्षेत्रों के सीमेंट स्टाकिस्टों के नाम और पते सूची में दिए गए हैं जो सभा पटल पर रख दिये गये हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी—555 77]

Purchase Scandal in D.T.C.

2122. SHRI GADADHAR SAHA:
SHRI BHAGAT RAM:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government propose to probe into the allegations of Rs. 1.25 crores purchase scandal in Delhi Transport Corporation; and

(b) if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The Stores and Purchase Committee of the